IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्त्तमान समय में डॉ० अम्बेडकर के आर्थिक विचार तथा भूमंडलीकरण – एक अध्ययन

राजेश्वर बैठा
विभागाध्यक्ष
अर्थशास्त्र विभाग
गोपेश्वर महाविद्यालय, हथुआ
(जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा)

डॉ० अम्बेडकर बहुआयामी ज्ञान से सम्पन्न प्रगतिशील बौद्धिक विचारक थे। वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली नेतृत्वकर्त्ता, कानूनविद् व सांसद के साथ–साथ प्रसिद्ध आर्थिक विचारक थे। उन्होंने प्रतिकूल सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति में अमेरिका क कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सन् 1915 ई० में अपने शोध–प्रबंध 'एन्शिऐंट इंडियन कॉमर्श' से एम० ए० एवं 1916 में 'नेशनल डिविजेन्ड ऑफ इण्डिया–ए हिस्टोरिकल एण्ड एनेलिटिकल स्टडी' में पी–एच०डी० की उपाधि से सम्मानित हुए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने अर्थशास्त्र के और भी गंभीर व सूक्ष्म अध्ययन हेतु 'लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस' में प्रवेश लिया। पुनः 1921 ई० में 'प्रोविन्सियल डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इंडिया' शोध पर एम०एस–सी० एवं 1922 ई० में 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी' पर डी०एस–सी० की उपाधि से विभूषित हुए।[1] इस प्रकार अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर

देश–दुनियाँ की अर्थव्यवस्था में प्रवीणता व विद्वता हासिल किये।

भारत गाँवों का देश है। यहाँ की लगभग 70% अर्थात् बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिसके आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। विश्व में जहाँ औसत 11 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, वही भारत में लगभग 52 प्रतिशत से अधिक भूमि कृषि योग्य है। विश्व के लगभग सभी जलवायु यहाँ उपलब्ध है साथ ही विश्व में पायी जाने वाली 60 प्रकार के मृदाओं में से करीब 46 प्रकार की मृदा भारत में उपलध हैं।[2] इतनी विविधता एवं क्षमता के बावजूद देश के बहुसंख्यक मजदूर–किसान खुशहाल नहीं हैं। गाँवों से शहरों विशेषकर महानगरों की ओर पलायन जारी है तथा कृषि पर आश्रित मजदूरों का जीवन अत्यन्त दयनीय एवं भयावह है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण, देशी राज्यों (रियासतों) की समाप्ति, भहदबदी कानून तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति आदि के साथ–साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण ने यह आशा और विश्वास जगायी थी कि अब सत्ता और संपत्ति का केन्द्र पूंजीपति और राजसत्ता से हटकर आमलोगों की ओर आएगी। किन्तु केन्द्रीकरण बढ़ता गया, भ्रष्टाचार में तीव्र वृद्धि हुई, गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी तथा विषमता का आर्थिक फैलाव (विस्तार) बढ़ता गया। पूंजीवादी और समाजवादी मॉडलों की अधूरी नकल (अंधानुकरण) ने नए वर्ग (शोषक), क्षेत्रीय असमानता, तनाव, असन्तोष व युद्ध जैसी स्थिति को जन्म दिया।

निःसन्देह फसलों का उत्पादन बढ़ा है, किन्तु भूमि सुधार के प्रयास लगभग असफल ही रहें। विदेशी ऋण पर आर्थिक विकास का नक्शा बनता रहा। यह देश की दुर्भाग्य ही है कि खाद्‌य समाग्रियों का भी आयात किया जा रहा है। किसानों का लागत मूल्य अर्थात एम०एस०पी० (Minimum Support Price) से भी वंचित किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन और वर्ल्ड बैंक दोनों का प्रभाव भारतीय कृषि नीति पर बढ़ता जा रहा है। विदेशी उत्पादों की खपत बढ़ रही है तथा परम्परागत उद्योग–धन्धे (स्वदेशी) नष्ट हो रहे हैं। ठाकुर दास बंग कहते हैं कि "अंग्रेजी शासन के डेढ़ सौ वर्षों में भारत के गाँवों के जितने उद्योग धन्धे नष्ट हुए, उससे अधिक पिछले वर्षों में स्वराज्य के बाद समाप्त हुए।"[3]

वर्त्तमान भूमंडलीकरण 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की आदर्श से अनुप्रेरित न होकर बाजार की बेलगाम व बेपरवाह शक्तियों के सहारे पश्चिम के प्रभुत्वशाली मंसूबों को पूरा करने की एक कुटिल प्रक्रिया है। इसने राजनीति अर्थव्यवस्था, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति आदि हर क्षेत्र को अपनी गोद में लिया है। भूमंडलीकरण के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों क बाजार पर अधिपत्य जमाना चाहते हैं। अपने उत्पादों तथा निवेशकों के लिए विकासशील देशों के दरवाजे हमेशा खुले रखने तथा विकासशील देशों के उत्पादों पर नए–नए बहाने बनाकर रोक (प्रतिबंध) लगाने संबंधी नियम बनाते रहते हैं।[4]

डॉ० अम्बेडकर ने "स्मॉल हाल्डिंग इंडिया एण्ड देअर रेमेडीज में अपने विचार व्यक्त किया था कि कृषि युक्त जमीन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अर्थात् सरकार सभी जमीन अधिकृत करेगी ताकि फैक्ट्री प्रोडक्ट्स कम लगे और आउरपुट ज्यादा आये।[5] किन्तु सरकार इसके स्थान पर विशेष आर्थिक जोन (सेज) बनायी है, जिसके अन्तर्गत सरकार हजारों एकड़ जमीन अधिकृत करेगी। उसमें जो प्लांट, फर्म, उद्योग, गोदाम, मॉल आदि बनेगी उसे कौड़ी के भाव साथ ही वैट या टैक्स से युक्त की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर विशेष आर्थिक क्षेत्र देश नामी–गिरामी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए है, क्योंकि गाँव के गरीब मजदूर–किसान के पास इतने धन नहीं कि कोई प्लांट, फर्म या उद्योग लगा सके।

अपने प्रसिद्ध शोध प्रबन्ध 'द प्रोब्लेम ऑफ द रूपी' में उन्होंने भारत में करेन्सी का प्रार्दुभाव कैसे हुआ? का जिक्र किया है। आज दो हजार और पाँच सौ का नोट हमारे जेब में है, जबकि हमारे पास उतना सोना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस है। ग्लोबल क्राइसिस होते हुए भी भारत के रुपया का मूल्य नीचे होते जा रहा है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर ज्यादा मजबूत है। अम्बेडकर साहब ने "रेव्हेल्यूशन ऑफ प्रोविन्शियल फाइनांस ऑफ ब्रिटिश इंडिया" स्पष्ट कहा है कि सरकार को सामाजिक कल्याण और शिक्षा के लिए

सबसे ज्यादा बजट में प्रावधान रखना चाहिए। उनका मत था कि केवल शिक्षा नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा (quality full education) लेना चाहिए।[6] शिक्षा समयानुकूल होना चाहिए किन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षा तो सरकार प्रदान करती नहीं। नीजी क्षेत्र के जितने की संस्थान हैं, वहाँ बाजारवाद प्रभावी है और पैसे का खेल हावी है।

भारतीय संविधान का उद्देश्य संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि भारत के आम नागरिक विशेषकर कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय तथा मानवीय गरिमा प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावना में जो सामाजिक–आर्थिक न्याय है, वह सीधे नीति निर्देशक तत्वों से निर्देशित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग–4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लेखित है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कह गया है कि आम लोगों (दलित–शोषित–मजदूर और किसान) के उत्थान के लिए राज्य को कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने चाहिए।[7] डॉ० अम्बेडकर को यह समझ रहे थे कि यदि सत्ता में काबिज तत्व न्याय एवं इन्सानियत के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, जिसकी और संविधान संकेत करता है, तो पूंजीवाद के काले बादल राजनीतिक प्रजातंत्र को घूमिल कर देंगे। जो वर्त्तमान समय में दिख भी रहे हैं। डॉ० अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय देशवासियों और उनके द्वारा गठित राजनीतिक दलों को सचेत किया था कि वे राष्ट्र की एकता एवं मजबूती को बनाये रखने के

लिए आम आदमी (Weeker section) की समृद्धि एवं खुशहाली का ध्यान अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों में अवश्य रखें, नहीं तो लोकतंत्र का महल जो बड़े परिश्रम से निर्मित किया है, वह ढ़ह जायेगा।[8]

डॉ० अम्बेडकर ने भारत के निर्धनता निरक्षरता, अशिक्षा, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता, कृषि पिछड़ापन, तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या के लिए राज्य समाजवाद को सामाजिक पुर्ननिर्माण के लिए आवश्यक बतलाया। वे मानते थे कि निर्धनता एवं बेरोजगारी की का एक मात्र समाधान औद्योगीकरण है तथा लगभग समस्त श्रमिकों की संख्या का 60 प्रतिशत खेतीहर मजदूरों की जीवन में तरक्की के लिए कृषि को उद्योग का रूप देकर उसे विभिन्न उद्योगों की भांति विकसित किया जाए। साथ ही समान कार्य–समान वेतन को व्यवहारिक बनाकर महिला श्रमिक के साथ होने वाले आर्थिक विभेद को समाप्त किया जाए साथ ही यह भी ध्यान दिया जाय कि बाल–श्रम जहाँ बहुत आवश्यक हो वहाँ उत्तम सुविधाऐं प्रदान कर उसे सक्षम एवं प्रशिक्षित किया जाय। देश की नई उभरती समाज व्यवस्था एवं आर्थिक उन्नति के लिए जीवन बीमा तथा अन्य प्रकार के बीमा प्रावधानो का अनिवार्य बनाना चाहिए।[9] डॉ० अम्बेडकर की मान्यता थी कि राजनीतिक प्रजातंत्र को आर्थिक प्रजातंत्र से जोड़ना चाहिए।[10] किन्तु ऐसा हो नहीं सका जिसके मुख्य कारण राजनीति का बाहुबलीकरण व अपराधीकरण, नेतृत्व मष्टता व अकुशलता, शीर्ष नेताओं

की आर्थिक–घोटालों में संलिप्तता तथा नौकरशाही की उदासीनता के साथ–साथ राष्ट्रीय आय के वितरण की दोषमुक्त व्यवस्था है।

आज भूमंडलीकरण के दुष्परिणामों के साथ–साथ इसका खोखलापन भी खुलकर सामने दिख रहा है। इसके कारण न केवल अविकसित एवं विकासशील देशों बल्कि तथाकथित विकसित देशों में भी बेरोजगारी एवं विषमता बढ़ रही है। इसे लेकर जगह–जगह असन्तोष बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग समझने लगे हैं कि भूमंडलीकरण द्वारा 'प्रायोजित विकास' एक हलावा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्रक्रिया गरीबी, भूखमरी (पाँच किलो राशन), बेरोजगारी, शोषण, विषमता एवं हिंसा का ही भूमंडलीकरण है।

असल में भूमंडलीकरण एक वैश्विक ब्राह्मणवाद है।[11] यह भारतीय समाज की विभेदमूलक वर्णव्यवस्था एवं जाति–व्यवस्था की तरह ही स्तरीय असमानता बढ़ावा देती है। इसके कारण व्यक्ति–व्यक्ति, वर्ग–वर्ग और राष्ट्र–राष्ट्र के बीच विषमता एवं द्वेष की खाई दिनोदिन चौड़ी और गहरी होती है जा रही है। जैसे एक ओर अमेरिका दुनिया के संसाधनों का एक बड़ा भाग का उपभोग कर रहा है, वहीं अधिकांश अफ्रीकी देशों को अपने अस्तित्व बचाने को संकट है। दुनियाँ भर में अरबपतियों की बढ़ती संपत्ति और इमारतों की बढ़ती ऊँचाई के साथ ही 'गरीबों और

बात यह है कि आज बाजारवाद, भोगवाद एवं उपभोक्तावाद की एक अंधी दौड़ चली है, जिसमें मानवीय एवं नैतिक मूल्यों, संस्कारों एवं सामाजिक सरोकारों के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

संक्षेप में यह दृष्टिगत है कि जिन देशों ने भूमंडलीकरण के जरिए तथाकथित आर्थिक–समृद्धि पायी है, वहाँ भी सामाजिक न्याय के दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है बल्कि इसके विपरित वहाँ आंतरिक जनतंत्र, मानवाधिकार एवं समानता की बली चढ़ाई गई है। अतः भारत जैसे विकासशील एवं अविकसित देशों को भूमंडलीकरण रूपी स्वर्णभेषी 'मारीच'[12] से सावधान रहने की जरूरत है।

डॉ० अम्बेडकर अपने आर्थिक विचारों में समाजवादी ढाँचे पर बल दिया था, ताकि निर्धन और कमजोर वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठे। किन्तु आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं में निरंतर उपेक्षा एक गंभीर विषय है। भूमंडलीकरण का मूलमंत्र जॉब विद्आउट इम्पलाइमेंट, ग्रोथ विद्आउट इन्वेस्टमेन्ट और यूज एण्ड थ्रो है।

कहना न होगा कि नये आर्थिक सुधार समाज के केवल 15 प्रतिशत लोगों को लाभ देने के लिए है, जो पहले से आर्थिक संपन्न है। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं से भारी ऋण लिए जा रहे है और वे अपनी दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था का संचालित चलाना चाहते हैं। यही कारण है कि स्वदेशी तथा विदेशी

गठबंधन पर आधारित नया पूंजीवाद बढ़ रहा है, जिसकी आड़ में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियाँ अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर रही है।

अतः कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्त्तमान आर्थिक सुधार आमजन की भावनाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पाश्चात्यीकरण, गैट पर हस्ताक्षर, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता आम जन मानस की समझ से परे है, क्योंकि आमलोग को तो दाल–रोटी, नमक–चीनी, सब्जी–तेल, आटा–चावल, कपड़े आदि कम कीमत पर चाहिए, जो बढ़ती महंगाई में असंभव बनता जा रहा है।

सन्दर्भ सूची :–

1. जाटव, डी०आर० (प्राक्कथन), डॉ० अम्बेडकर के आर्थिक विचार, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1996, पृ०–VI
2. कुमार मुकेश एवं सुधांशु शेखर (संपादक), भूमंडलीकरण नीति और नियति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर (म० प्र०) 2009, पृ०–178
3. बंग, ठाकुरदास, भारत की घर, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, मार्च, 1988, पृ०–39
4. भूमंडलीकरण नीति और नियति, पृ०–179
5. मेहरा, एड भूपसिंह (सं०) मूलनिवासी टाइम्स, भानकपुरा, नई दिल्ली, 110005, 16 से 31 मई, 2009, पृ०–56
6. *वही*, पृ०–56

7. *वही,* पृ०–63

8. अम्बेडकर के आर्थिक विचार, पृ०–122

9. *वही,* पृ०–119–20

10. *वही,* पृ०–122

11. भूमंडलीकरण नीति और नियति, पृ०–146

12. शेखर, सुधांशु, वैश्वीकरण और विश्वशांति, दार्शनिक अनुगूंज, सं–डॉ० श्यामल किशोर, बिहार दर्शन परिषद् पटना (बिहार) वर्ष–3, अंक–1, जनवरी–जून, 2009, पृ०–190

IJCRT